AGRASEN CIVIL SERVICES ACADEMY

Where tradition meets innovation

ACSA

15 से 21 अगस्त 2023

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

For

UPSC / RPSC EXAMS

and All Other Competitive

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
- नशीली दवाओं की जब्ती चार्ट पर शीर्ष राज्य
- महाराष्ट्र के लिए निजी कंपनी से की साझेदारी कुंभ 2025 आवास
- कक्षा 3-12 के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यपुस्तक पैनल
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट " विंध्यगिरि " लॉन्च करेंगे
- भारत ने आपराधिक कानूनों में बदलाव किया
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कच्चे तेल के लेनदेन के निपटान के लिए एलसीएस प्रणाली

GST

GOODS AND SERVICES TAX

A UNIT OF
AGRAWAL PG COLLEGE
Affiliated to University of Rajasthan | Managed by Shri Agrawal Shiksha Samiti
(A Co-Educational College)

+91-8824395504, +91-8290664069
www.acsajaipur.com
Agrasen Katla, Maharaja Agrasen Marg,
Agra Road, Jaipur - 302003

करेंट अफेयर्स 15 से 21 अगस्त 2023

संक्षिप्त:-

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
- नशीली दवाओं की जब्ती चार्ट पर शीर्ष राज्य
- महाराष्ट्र के लिए निजी कंपनी से की साझेदारी कुंभ 2025 आवास:
- कक्षा 3-12 के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यपुस्तक पैनल
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट " विंध्यगिरि " लॉन्च करेंगे
- पाकिस्तानी सीनेटर अनवर-उल-हक कक्कड़ को केयरटेकर प्रीमियर नामित किया गया
- भारत ने आपराधिक कानूनों में बदलाव किया
- मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कच्चे तेल के लेनदेन के निपटान के लिए एलसीएस प्रणाली
- फ्लडवॉच मोबाइल ऐप
- नदियों का नहरीकरण
- एनईएसआईडीएस और एनईसी की योजनाओं को जारी रखना
- ब्रिक्स की नई यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रणाली

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, हाल ही में लोक में पेश किया गया सभा , केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के तहत कराधान ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करती है। विधेयक निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों और ऑनलाइन मनी गेमिंग के कराधान पर केंद्रित है। वर्तमान सीजीएसटी अधिनियम के तहत, कुछ गतिविधियों को छोड़कर, कार्रवाई योग्य दावों से जुड़े लेनदेन को आपूर्ति नहीं माना जाता है और इस प्रकार कर योग्य नहीं होता है।

नया संशोधन सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़, लॉटरी, जुआ और ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसी गतिविधियों से जुड़े निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के आपूर्तिकर्ताओं पर सीजीएसटी लगाते हुए दायरे का विस्तार करता है। बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग की परिभाषा और आपूर्तिकर्ताओं के रूप में कौन योग्य है, इसकी रूपरेखा बताता है। इसके अतिरिक्त, बिल भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदान करने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है और ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में कुल दांव मूल्य पर 28% कर का प्रस्ताव करता है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 कार्रवाई योग्य दावों के कराधान को कैसे संशोधित करता है?

यह बिल सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़, लॉटरी, जुआ और ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसी गतिविधियों से संबंधित निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों को सीजीएसटी के दायरे में लाकर कर योग्य लेनदेन के दायरे का विस्तार करता है। पहले, कुछ गतिविधियों को छोड़कर, कार्रवाई योग्य दावों को आपूर्ति नहीं माना जाता था और इस प्रकार कर योग्य नहीं था। संशोधन में उल्लिखित गतिविधियों से जुड़े निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के आपूर्तिकर्ताओं पर सीजीएसटी लगाकर इसे बदल दिया गया है।

बिल के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग की परिभाषा क्या है?

ऑनलाइन मनी गेमिंग, जैसा कि बिल द्वारा परिभाषित किया गया है, ऑनलाइन गेम को संदर्भित करता है जहां खिलाड़ी पैसे या उसके समकक्ष मूल्य जीतने की उम्मीद के साथ आभासी डिजिटल संपत्ति सहित पैसा जमा करते हैं। इस परिभाषा में कौशल, मौका या दोनों के संयोजन के खेल शामिल हैं, चाहे किसी भी कानून के तहत अनुमति हो या प्रतिबंधित हो, और इसमें इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर पेश किए गए गेम शामिल हैं।

संशोधित सीजीएसटी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों का आपूर्तिकर्ता किसे माना जाएगा?

बिल ऐसे व्यक्ति पर विचार करता है जो निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का आयोजन या सुविधा प्रदान करता है, जिसमें ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें अपना आपूर्तिकर्ता मानता है। यह वर्गीकरण इस पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि आपूर्ति के लिए प्रतिफल किस प्रकार व्यक्त किया गया है या व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया है और इसमें मौद्रिक मूल्यों के साथ-साथ आभासी डिजिटल संपत्ति भी शामिल है।

भारत के बाहर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदाताओं के लिए विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

विधेयक में कहा गया है कि भारत में व्यक्तियों को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाली विदेशी संस्थाओं को सीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना होगा। यह प्रावधान ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल अपतटीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए कराधान की पहुंच का विस्तार करता है।

ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए प्रस्तावित कर दर क्या है?

बिल में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में कुल दांव मूल्य पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है। यह इन गतिविधियों के कराधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से राजस्व उत्पन्न करना है।

यह बिल ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के अनुपालन को कैसे संबोधित करता है?

बिल में पंजीकरण और कर भुगतान आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहने पर विदेशों में स्थित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के प्रावधान शामिल हैं। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाली ऑफशोर संस्थाएं सीजीएसटी अधिनियम द्वारा निर्धारित कराधान और नियामक ढांचे का पालन करती हैं।

नशीली दवाओं की जब्ती चार्ट पर शीर्ष राज्य

पिछले तीन वर्षों में, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने विभिन्न भारतीय राज्यों से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित पंजाब और राजस्थान में हेरोइन की सबसे अधिक बरामदगी देखी गई है, जबकि भारत-बांग्लादेश सीमा के पास त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल 'गांजा' के मामले में शीर्ष पर हैं । ज़ब्ती. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इन निष्कर्षों को राज्य में प्रस्तुत किया सभा , जब्त की गई मात्राओं और देखे गए रुझानों का विवरण देती है। रिपोर्ट में आगे की जांच के लिए जब्त किए गए पदार्थों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने पर भी प्रकाश डाला गया है। संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उन्नत उपकरणों की तैनाती सहित मजबूत निगरानी उपायों को अपनाया गया है।

पंजाब और राजस्थान में सबसे ज्यादा हेरोइन की बरामदगी क्यों हुई है?

पंजाब और राजस्थान में हेरोइन की महत्वपूर्ण बरामदगी का श्रेय भारत-पाकिस्तान सीमा से उनकी निकटता को दिया जा सकता है, जो सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बढ़ाए गए सुरक्षा फोकस का उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों को रोकना है।

त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की ' गांजा ' जब्ती को प्रमुखता देने में कौन से कारक योगदान करते हैं?

गांजा ' बरामदगी में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की प्रमुखता भारत-बांग्लादेश सीमा पर उनके स्थान से जुड़ी हुई है। तस्करी के प्रति सीमा की संवेदनशीलता ' गांजा ' जैसे नशीले पदार्थों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है , जिससे प्रवर्तन प्रयासों में वृद्धि होती है।

बरामदगी के बाद बीएसएफ अन्य एजेंसियों के साथ कैसे सहयोग करती है?

ड्रग्स जब्त करने के बाद, बीएसएफ आगे की जांच के लिए राज्य पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि नशीली दवाओं के तस्करों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा एजेंसियों के पास क्या शक्तियाँ हैं?

1985 का नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को एसएसबी, असम राइफल्स और भारतीय तट रक्षक जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर स्थलीय और समुद्री सीमाओं पर मादक दवाओं के पारगमन को कानूनी रूप से रोकने का अधिकार देता है। यह उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सशक्त बनाता है।

नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए निगरानी और प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा रहा है?

सीमा पर भेद्यता मानचित्रण और उन्नत निगरानी तकनीकें, जैसे हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स, नाइट विजन डिवाइस, यूएवी और रडार सिस्टम तैनात किए गए हैं। यह तकनीक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता करती है और अवैध गतिविधियों की रोकथाम को बढ़ाती है।

एकीकृत निगरानी तकनीक का सीमा सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है?

सीसीटीवी/पीटीजेड कैमरे, आईआर सेंसर और इन्फ्रारेड अलार्म से सुसज्जित एकीकृत निगरानी तकनीक ने वास्तविक समय की निगरानी और अलर्ट प्रदान करके सीमा सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार किया है। इससे तस्करी के संभावित प्रयासों पर त्वरित प्रतिक्रिया समय सक्षम हो गया है।

महाराष्ट्र के लिए निजी कंपनी से की साझेदारी कुंभ 2025 आवास:

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के दौरान लगभग 5,000 विशेष आवास उपलब्ध कराने के लिए एक निजी फर्म के साथ एक समझौता किया है। महा 2025 में कुंभ। होमस्टे, बिस्तर और नाश्ता प्रतिष्ठान और पेइंग गेस्ट इकाइयों सहित ये आवास राज्य के प्रमुख शहरों और प्रमुख स्थानों में फैले होंगे। पर्यटन निदेशालय और लुज़र्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओजीए) ने इस पहल पर सहयोग करने के लिए एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पांच वर्षों तक चलने वाले इस एमओयू का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के आवासों की पेशकश करके पर्यटन को बढ़ाना है। महा के दौरान आने वाली भारी भीड़ के लिए आवास की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कुम्भ मेला 2025, प्रयागराज ।

उत्तर प्रदेश सरकार और एक निजी कंपनी के बीच साझेदारी महाराष्ट्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कुंभ 2025?

महा के दौरान आने वाले आगंतुकों की बड़ी संख्या की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कुम्भ मेला 2025, प्रयागराज ।

महा के दौरान किस प्रकार के आवास की पेशकश की जाएगी कुम्भ ?

आवास में होमस्टे, बिस्तर और नाश्ता प्रतिष्ठान और भुगतान अतिथि इकाइयाँ शामिल होंगी, जो आगंतुकों के लिए विविध प्रकार के विकल्प सुनिश्चित करेंगी।

क्यों है प्रयागराज महा कुंभ को माना जाता है बड़ा आयोजन?

प्रयागराज _ महा कुंभ एक महत्वपूर्ण धार्मिक समागम है जहां लाखों हिंदू तीर्थयात्री स्नान अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसका अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है।

कुंभ के कारण प्रयाग (इलाहाबाद), हरद्वार, उज्जैन और नासिक के स्थल रहस्यमय क्यों माने जाते हैं? मेला ?

ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों ने रहस्यमय शक्ति प्राप्त कर ली है क्योंकि वैदिक साहित्य के अनुसार, दूध सागर के मंथन के दौरान निकली अमर अमृत की बूंदें इन स्थानों पर छिपी हुई थीं।

सरकार और एक निजी फर्म के बीच साझेदारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य को कैसे प्रभावित करती है?

यह साझेदारी आगंतुकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उपयुक्त आवास प्रदान करके उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह महा जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है कुंभ .

कक्षा 3-12 के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यपुस्तक पैनल

स्कूली शिक्षा पर भारत की शीर्ष सलाहकार संस्था ने कक्षा 3-12 के लिए स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के साथ संरेखित करने के लिए 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। फ़ील्ड्स पदक विजेता मंजुल -भार्गव , अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय , परोपकारी सुधा मूर्ति , और गायक शंकर महादेवन समिति के सदस्यों में से हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) के चांसलर एमसी पंत के नेतृत्व वाली समिति का लक्ष्य कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकों को भी संशोधित करना है। एनसीएफ स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश करता है, जिसमें द्वि-वार्षिक बोर्ड परीक्षा, 12वीं कक्षा के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली और छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता शामिल है। समिति में अर्थशास्त्र, शिक्षा, खेल और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

नव स्थापित समिति भारत में शिक्षा सुधार में कैसे योगदान देती है?

समिति का उद्देश्य स्कूल के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के साथ संरेखित करना है, जो व्यापक शिक्षा सुधार को बढ़ावा देता है। यह शैक्षिक सामग्री को आधुनिक शिक्षण लक्ष्यों और पद्धतियों के साथ संरेखित करता है, और अधिक प्रासंगिक और प्रभावी पाठ्यक्रम को बढ़ावा देता है।

मंजुल जैसे प्रमुख व्यक्तियों की क्या भूमिका है? भार्गव और सुधा मूर्ति समिति में खेलते हैं?

फ़ील्ड्स मेडल विजेता गणितज्ञ, भार्गव और जाने-माने परोपकारी मूर्ति, पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि लाते हैं। उनके विविध दृष्टिकोण शिक्षा सामग्री को आकार देने में समिति के दृष्टिकोण को समृद्ध करते हैं।

समिति का कार्य कक्षा 1 और 2 से उच्च ग्रेड में संक्रमण करने वाले छात्रों को कैसे प्रभावित करेगा?

कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने की समिति की योजना छात्रों के लिए उच्च ग्रेड में निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करती है। यह संरेखण प्रारंभिक शिक्षा और उन्नत स्तरों के बीच अंतर को पाटता है, जिससे सीखने में निरंतरता और सुसंगतता को बढ़ावा मिलता है।

प्री-ड्राफ्ट एनसीएफ की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

प्री-ड्राफ्ट एनसीएफ शिक्षा में कई परिवर्तनकारी बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिसमें द्वि-वार्षिक बोर्ड परीक्षा, कक्षा 12 के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली और छात्रों के लिए विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य जैसे विषयों को चुनने के लिए अधिक लचीलापन शामिल है। हालाँकि, अंतिम रिपोर्ट की विस्तृत सिफ़ारिशों का खुलासा होना अभी बाकी है।

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने से पाठ्यक्रम विकास में क्या लाभ होता है?

समिति के सदस्य अर्थशास्त्र, साहित्य, खेल और शिक्षा सहित विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। यह विविधता पाठ्यक्रम विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण और विशेषज्ञता शामिल होती है।

समिति की संरचना शिक्षा सुधार के प्रति उसके समर्पण को कैसे दर्शाती है?

मंजुल जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हैं भार्गव , जो एक प्रमुख गणितज्ञ हैं, और सुधा मूर्ति , शिक्षा के प्रति समर्पित एक परोपकारी व्यक्ति थे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का समावेश, भारत की शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट " विंध्यगिरि " लॉन्च करेंगे

राष्ट्रपति द्रौपदी भारतीय नौसेना की घोषणा के अनुसार, मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट विंध्यगिरी को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं । इस युद्धपोत का नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और यह प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट कार्यक्रम के तहत छठा जहाज है। इस पहल में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा चार और जीआरएसई द्वारा तीन जहाजों का निर्माण शामिल है । प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स से प्रेरित ये तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस हैं। यह प्रक्षेपण घरेलू कंपनियों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ, अपनी नौसैनिक विरासत और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

भारत की नौसैनिक रणनीति में प्रोजेक्ट 17ए युद्धपोत का क्या महत्व है?

प्रोजेक्ट 17ए युद्धपोत भारत के नौसैनिक बेड़े के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इन जहाजों को उन्नत प्रौद्योगिकियों, गुप्त क्षमताओं और स्वदेशी प्रणालियों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

विंध्यगिरि युद्धपोत का प्रक्षेपण क्यों उल्लेखनीय है?

विंध्यगिरि युद्धपोत का प्रक्षेपण भारत के नौसैनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया, यह अत्याधुनिक नौसैनिक प्रौद्योगिकी के साथ भारत की समुद्री विरासत के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रोजेक्ट 17ए युद्धपोतों को उनके पूर्ववर्तियों से क्या अलग करता है?

शिवालिक क्लास पर आधारित प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स में बेहतर स्टील्थ क्षमताएं, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियां हैं, जो उनकी परिचालन प्रभावशीलता और रणनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ाती हैं।

प्रोजेक्ट 17ए कार्यक्रम में स्वदेशी फर्मों की भागीदारी कैसे योगदान देती है?

प्रोजेक्ट 17ए जहाजों के लिए घटकों और प्रणालियों की लगभग 75% मांगें घरेलू कंपनियों से खरीदी जाती हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं। यह दृष्टिकोण घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देता है और आयात पर निर्भरता कम करता है।

नए युद्धपोत के पूर्ववर्ती आईएनएस विंध्यगिरि की क्या भूमिका थी ?

आईएनएस विंध्यगिरि , एक लिएंडर क्लास एएसडब्ल्यू फ्रिगेट, ने लगभग 31 वर्षों तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, समुद्री निगरानी, तटीय गश्त और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में उत्कृष्टता के साथ सेवा की। इसे एक ऐसे पूर्ववर्ती के रूप में याद किया जाता है जिसने भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विंध्यगिरि का प्रक्षेपण भारत की नौसैनिक आकांक्षाओं में कैसे योगदान देता है?

विंध्यगिरि का प्रक्षेपण अपनी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए अपनी नौसैनिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति भारत के समर्पण का प्रतीक है। यह तकनीकी उन्नति, आत्मनिर्भरता और अपने समुद्री हितों की सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

पाकिस्तानी सीनेटर अनवर-उल-हक कक्कड़ को केयरटेकर प्रीमियर नामित किया गया

पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से केवल तीन दिन पहले देश की संसद को भंग करने के आश्चर्यजनक फैसले के कारण सीनेटर अनवर-उल-हक की नियुक्ति हुई है। कक्कड़ कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। राजनीतिक हलकों में एक अपेक्षाकृत अज्ञात व्यक्ति काकर , बलूचिस्तान से हैं , जो आंतरिक उथल-पुथल वाला प्रांत है। उनकी नियुक्ति ने उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब उन्हें संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करनी है।

अनवार-उल-हक बलूचिस्तान के 52 वर्षीय काकर कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में एक आश्चर्यजनक पसंद हैं। उन्होंने 2018 से पाकिस्तान की सीनेट में सेवा की है और बलूचिस्तान का हिस्सा थे अवामी पार्टी (बीएपी), सेना से निकटता के लिए जानी जाती है। राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी, फिर भी उनकी सापेक्ष अस्पष्टता इस भूमिका के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाती है।

पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार की जिम्मेदारियाँ क्या हैं?

पाकिस्तान का संविधान संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार को राष्ट्रीय चुनावों की निगरानी करने का आदेश देता है। कार्यवाहक सरकार का प्राथमिक कार्य निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, जो आर्थिक निश्चितता के लिए महत्वपूर्ण स्थिरता प्रदान करती है।

पाकिस्तान की संसद समय से पहले क्यों भंग कर दी गई?

अपना कार्यकाल पूरा करने के करीब होने के बावजूद, संसद को भंग करने का निर्णय मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के कारण हो सकता है। भ्रष्टाचार के आरोपों में इमरान खान की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि, कार्यवाहक सरकार को अधिक अधिकार देने वाले विधायी परिवर्तनों के साथ मिलकर, इस निर्णय में योगदान दे सकते थे।

कक्कड़ की नियुक्ति का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है ?

कक्कड़ की नियुक्ति कार्यवाहक सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। विपक्ष, विशेष रूप से पीटीआई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करता है, जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक निश्चितता के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल के विधायी परिवर्तन कार्यवाहक सरकार की भूमिका को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?

हाल के विधायी परिवर्तन कार्यवाहक सरकार को नियमित मामलों से परे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। सत्ता के इस विस्तार के साथ-साथ सेना समर्थित कार्यवाहक प्रधानमंत्री के संभावित प्रभाव ने पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव की अटकलों को हवा दे दी है।

2023 की डिजिटल जनगणना संसद भंग करने में क्या भूमिका निभाती है?

डिजिटल जनगणना, जिसे "इंटरेस्ट काउंसिल" द्वारा जल्दबाजी में मंजूरी दे दी गई, ने 2017 में जनसंख्या 21 करोड़ से बढ़कर 2023 में 24 करोड़ होने का खुलासा किया। यह अगले चुनावों से पहले जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अनिवार्य करता है, जिससे संभावित रूप से देरी हो सकती है।

भारत ने आपराधिक कानूनों में बदलाव किया

भारत एक बड़े कानूनी परिवर्तन के लिए तैयार है क्योंकि इसकी आपराधिक न्याय प्रणाली को उभरते सामाजिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रमुख कानूनों को बदलने की तैयारी है। प्रस्तावित सुधारों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 को भारतीय दंड संहिता से बदलना शामिल है न्याय संहिता (बीएनएस), राज्य के खिलाफ अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और हत्या को प्राथमिकता देती है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है भारतीयता नागरिक सुरक्षा विधेयक, जिसका उद्देश्य बढ़ी हुई नागरिक सुरक्षा के लिए आपराधिक कार्यवाही को सुव्यवस्थित करना है। भारतीय _ साक्ष्य विधेयक अदालत में साक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए साक्ष्य नियमों पर केंद्रित है। ये सुधार सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में पेश करते हैं और नागरिकों के अधिकारों और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। कानूनी विशेषज्ञों, सांसदों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करने वाली सावधानीपूर्वक योजना सुधार के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण पर जोर देती है।

ये कानूनी सुधार भारत के कानूनी परिदृश्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

ये सुधार भारत के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं, इसे आधुनिक सामाजिक मूल्यों के साथ संरेखित किया गया है। आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 जैसे प्रमुख कानूनों को बदलना एक कुशल और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह बदलते समय के साथ विकसित हो।

भारतीयता के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? न्याय संहिता (बीएनएस)?

बीएनएस का लक्ष्य अपराधों के वर्गीकरण और सजा में सुधार करना है। यह राज्य के ख़िलाफ़ अपराध, महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध और हत्या को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा, यह आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी समसामयिक चुनौतियों का समाधान करता है, जबकि धारा 377 को हटाकर यौन उत्पीड़न के शिकार पुरुषों के बारे में चिंताएं बढ़ाता है।

भारतीय कैसा है नागरिक सुरक्षा विधेयक नागरिक सुरक्षा में योगदान देगा?

भारतीय _ नागरिक सुरक्षा विधेयक आपराधिक कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने, अधिक कुशल कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिक सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करता है। यह एक न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय की क्या भूमिका है? साक्ष्य विधेयक प्रस्तावित सुधारों में भूमिका निभाएगा?

भारतीय _ साक्षी विधेयक साक्ष्य-संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो आपराधिक मुकदमों के लिए मौलिक हैं। साक्ष्य एकत्र करने और मूल्यांकन के प्रति इसके आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों की विश्वसनीयता में सुधार करना है।

सज़ा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरूआत आधुनिक रुझानों के साथ कैसे मेल खाती है?

सामुदायिक सेवा की शुरूआत दंडात्मक उपायों में एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाती है। छोटे अपराधों के लिए दंड के साथ पुनर्वास को जोड़कर, भारत समाज की उभरती गतिशीलता को स्वीकार करता है और अधिक संतुलित और प्रभावी न्याय प्रणाली के लिए प्रयास करता है।

सुधार प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, कानूनी विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे हितधारकों की भागीदारी प्रस्तावित सुधारों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करती है। यह दृष्टिकोण एक सर्वांगीण परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देता है और संभावित नुकसान से बचने में मदद करता है, जिससे अधिक प्रभावी कानूनी परिवर्तन होता है।

मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ

भारत के राष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ज्ञात और अज्ञात नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें मातंगिनी भी शामिल हैं हाजरा और कनकलता बरुआ , उल्लेखनीय महिलाएँ जिन्होंने आंदोलन में अमिट योगदान दिया। मातंगिनी पश्चिम बंगाल की एक बहादुर आत्मा हाजरा ने ब्रिटिश उत्पीड़न से लड़ते हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, गिरफ्तारियां दीं और अंततः 1942 में अपनी जान दे दी। कनकलता असम की एक प्रतिष्ठित शख्सियत बरुआ ने 1942 में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच तिरंगा फहराया और सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गए। उनका बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का प्रतीक है। यह लेख उनके असाधारण जीवन, उनके लचीलेपन और इतिहास के पन्नों पर उनके द्वारा छोड़े गए स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

मातंगिनी हाजरा पश्चिम बंगाल के एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सहित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। कनकलता दूसरी ओर, बरुआ असम के एक युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया था। दोनों महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया।

मातंगिनी ने कैसे किया? हाजरा का प्रारंभिक जीवन एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी यात्रा को आकार देता है?

एक गरीब परिवार में जन्मी और कम उम्र में ही मातंगिनी से शादी हो गई हाजरा को चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे उनका संकल्प मजबूत हुआ। अपने पति की मृत्यु के बाद, उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और अंततः महात्मा गांधी के सिद्धांतों के साथ जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार बन गईं।

कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ मातंगिनी को चिन्हित करती हैं स्वतंत्रता संग्राम में हाजरा की भागीदारी?

मातंगिनी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हाजरा की सक्रिय भूमिका, नमक मार्च में भागीदारी और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। एक पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा करने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व करते समय उनके सर्वोच्च बलिदान ने उनकी अदम्य भावना का प्रदर्शन किया।

मातंगिनी ने कैसे किया? हाजरा और कनकलता बरुआ ने भारत के इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ा?

मातंगिनी हाजरा के बलिदान ने उन्हें शहीद का दर्जा दिलाया और मेदिनीपुर में एक स्थानीय सरकार की स्थापना हुई । सड़कों, स्कूलों और मोहल्लों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। कनकलता बरुआ की विरासत उनके सम्मान में नामित तटरक्षक जहाज के माध्यम से जीवित है , जो असम के इतिहास में उनके स्थायी योगदान का प्रतीक है।

मातंगिनी क्या करती हैं? हाजरा और कनकलता बरुआ स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में प्रतिनिधित्व करते हैं?

दोनों महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उदाहरण हैं। उनके साहस, नेतृत्व और बलिदान ने रूढ़िवादिता को तोड़ दिया, और अधिक महिलाओं को इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानियाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कच्चे तेल के लेनदेन के निपटान के लिए एलसीएस प्रणाली

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके कच्चे तेल के लेनदेन को निपटाने का विकल्प चुनकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। इस ऐतिहासिक लेन-देन में भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम का उपयोग शामिल होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिशीलता में एक उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करेगा। इस परिवर्तनकारी परिवर्तन को स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) प्रणाली द्वारा सुगम बनाया गया है, जिसे एक के माध्यम से पेश किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र की यात्रा के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर मोदी यूएई गए. एलसीएस प्रणाली प्रभावी रूप से मध्यस्थ मुद्राओं की आवश्यकता को हटा देती है, जिससे लेनदेन के समय और संबंधित लागत दोनों में कमी आती है। इस अग्रणी कदम से आर्थिक सहयोग बढ़ने, आर्थिक लचीलापन मजबूत होने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत होने की उम्मीद है। सोने के व्यापार से जुड़े लेनदेन के साथ प्रणाली की सफलता पहले ही प्रदर्शित की जा चुकी है। चूँकि भारत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को बढ़ावा देना चाहता है, यह कदम नवीन व्यापार प्रथाओं के लिए एक मिसाल कायम करता है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं, भारतीय रुपया और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम का उपयोग करके कच्चे तेल के लेनदेन का निपटान करके एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य मध्यस्थ मुद्राओं की आवश्यकता को समाप्त करके आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और लेनदेन लागत को कम करना है।

स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) प्रणाली क्या है और यह कैसे काम करती है?

एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से शुरू की गई एलसीएस प्रणाली, रुपये और दिरहम का उपयोग करके भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेनदेन को सक्षम बनाती है। यह मध्यस्थ मुद्राओं पर निर्भरता को समाप्त करता है, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और लेनदेन के समय और लागत को कम करता है।

एलसीएस प्रणाली भारत और संयुक्त अरब अमीरात को क्या लाभ प्रदान करती है?

एलसीएस प्रणाली कई लाभ लाती है, जिसमें लेनदेन का समय और लागत कम करना, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक लचीलापन बढ़ाना शामिल है। यह दोनों देशों को विदेशी मुद्रा व्यय बचाने, आर्थिक सहयोग और स्थानीय संपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

एलसीएस प्रणाली का उपयोग करके अन्य किन वस्तुओं का व्यापार किया गया है?

कच्चे तेल के अलावा, सोने के व्यापार से जुड़े लेनदेन में एलसीएस प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के एक निर्यातक से भारत को 25 किलोग्राम सोने की बिक्री का चालान एलसीएस प्रणाली का उपयोग करके किया गया था, जो इसकी व्यवहार्यता साबित करता है।

यह कदम अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों से कैसे मेल खाता है?

भारत वैश्विक व्यापार में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ाने पर काम कर रहा है। विभिन्न देशों के बैंकों के साथ सहयोग में संलग्न होकर, भारत ने घरेलू बैंकों के भीतर समर्पित रुपया वोस्ट्रो खाते स्थापित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्राओं के व्यापार को सुव्यवस्थित करना है।

इस कदम से भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

संयुक्त अरब अमीरात के साथ एलसीएस प्रणाली को अपनाकर, भारत नवीन व्यापार प्रथाओं के लिए एक मिसाल कायम करता है जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को नया आकार दे सकता है। यह कदम वैश्विक व्यापार क्षेत्र में भारत की स्थिति को बढ़ाता है और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

फ्लडवॉच मोबाइल ऐप

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने ' फ्लडवॉच ' मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया है, जिससे सात दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इन-हाउस विकसित, ऐप सटीक बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग करता है। भारत भर में बाढ़ की स्थिति पर सुलभ जानकारी के साथ, ऐप अंग्रेजी और हिंदी में पठनीय और ऑडियो प्रसारण सहित उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाएं प्रदान करता है।

338 स्टेशनों का डेटा 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करेगा। ऐप की इंटरैक्टिव मानचित्र सुविधा उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट स्टेशनों, राज्यों या बेसिनों का चयन करके 24 घंटे या 7 दिनों तक सीडब्ल्यूसी बाढ़ पूर्वानुमान या बाढ़ सलाह की जांच करने की अनुमति देती है।

नदियों का नहरीकरण

पंजाब राज्य को हाल ही में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है। इस क्षेत्र की नदियाँ, जिनमें सतलज, ब्यास और रावी शामिल हैं, नालों और मौसमी धाराओं के साथ, इसके जल नेटवर्क में योगदान करती हैं। विशेषज्ञ बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए जल स्रोतों के प्रभावी विनियमन की वकालत करते हैं। नहरीकरण, चैनलों और संरचनाओं के माध्यम से जल प्रवाह को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, एक समाधान के रूप में प्रस्तावित है। जबकि पंजाब में प्रमुख बांध और तटबंध हैं, अंतर्निहित कमज़ोरियाँ उन्हें टूटने के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

नहरीकरण से पानी का रुख मोड़ा जा सकता है और बांधों से पानी छोड़े जाने का प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे एक व्यापक बाढ़ रोकथाम रणनीति की पेशकश की जा सकती है। हाल ही में नदियों और स्थानीय जलमार्गों के उफनने के कारण आई बाढ़, भारी वर्षा और बांधों से पानी के बहाव दोनों को प्रबंधित करने के लिए नहरीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक नहरीकरण रणनीतियों और मजबूत तटबंधों का सुझाव दिया जाता है।

पंजाब में बाढ़ के दो प्रमुख कारण क्या थे?

पंजाब में हाल की बाढ़ की घटनाओं के लिए भारी क्षेत्रीय वर्षा और बांधों से पानी छोड़ा जाना जिम्मेदार था।

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से निकलने वाली बारहमासी और गैर-बारहमासी नदियाँ पंजाब के जल नेटवर्क के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

ये नदियाँ पंजाब में मानसून के पानी का पर्याप्त योगदान देती हैं, और उनका अतिप्रवाह, खासकर जब बांध क्षमता से भरे होते हैं, स्थानीय वर्षा के बिना भी बाढ़ का खतरा पैदा करते हैं।

नहरबंदी क्या है और यह कैसे काम करती है?

नहरीकरण में जल प्रवाह को विशिष्ट चैनलों में निर्देशित करके नियंत्रित करना, छोटे बांधों का उपयोग करना, नहर प्रणालियों और नदियों को आपस में जोड़ना और तटबंधों को मजबूत करना शामिल है।

धुस्सी की कमजोरियां क्या हैं? बंद , और वे उल्लंघन के प्रति संवेदनशील क्यों हैं?

धूस्सी बांध प्रमुख नदियों के किनारे मिट्टी के तटबंध होते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं नदी के प्रवाह में मामूली वृद्धि के बावजूद भी उन्हें टूटने के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

बताएं कि नहरीकरण पंजाब में बाढ़ के खतरों को कैसे कम कर सकता है?

नहरीकरण से स्थानीय वर्षा जल के अतिप्रवाह और नियंत्रित बांध निकास दोनों को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, जो एक व्यापक बाढ़ रोकथाम रणनीति की पेशकश करेगी।

नहरीकरण के माध्यम से बाढ़ की रोकथाम के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

धुस्सी को मजबूत करने के साथ-साथ दीर्घकालिक नहरीकरण रणनीतियों का सुझाव देते हैं पंजाब में भावी बाढ़ आपदाओं को रोकने के लिए बंद ।

एनईएसआईडीएस और एनईसी की योजनाओं को जारी रखना

रुपये के बजट के साथ नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) को जारी रखने को हरी झंडी दे दी है । 2022-23 से 2025-26 के लिए 8139.50 करोड़। एनईएसआईडीएस में दो घटक शामिल हैं: एनईएसआईडीएस-रोड और एनईएसआईडीएस-रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (ओटीआरआई), दोनों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है। नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम (एनईआरएसडीएस) को एनईएसआईडीएस-रोड में विलय करने जैसे सरकारी फैसलों के कारण, पुनर्गठित एनईएसआईडीएस के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में चिन्हित क्षेत्रों, विशेष रूप से कनेक्टिविटी में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। समवर्ती रूप से, कैबिनेट ने रुपये आवंटित करते हुए 2022-23 से 2025-26 तक 'एनईसी की योजनाओं' को जारी रखने की मंजूरी दे दी । 3202.7 करोड़. ये योजनाएं केंद्रीय मंत्रालयों के प्रयासों की पूरक हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन योजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश, सहयोगात्मक प्रयासों के साथ मिलकर, अपने इच्छित उद्देश्यों को पारदर्शी और कुशलता से प्राप्त करना चाहते हैं।

ब्रिक्स की नई यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रणाली

ब्रिक्स देशों-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका- के शिक्षा मंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम मौजूदा रैंकिंग और उनके व्यापक डेटा की कमी के संबंध में आलोचनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उठाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के म्पुमलांगा प्रांत में आयोजित एक बैठक के दौरान, मंत्रियों ने आज के वैश्विक संदर्भ में एक विश्वसनीय और प्रासंगिक शिक्षा ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार किया।

यह पहल वर्तमान रेटिंग विधियों की सीमाओं को पहचानते हुए विभागीय नेताओं के बीच एक समझौते से उपजी है। रूस के विज्ञान और उच्च शिक्षा उप मंत्री, कॉन्स्टेंटिन मोगिलेव्स्की ने वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत डेटा के आधार पर एक नए मूल्यांकन ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सभी पांच देशों के शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने आगामी रेटिंग प्रणाली के लिए गुणात्मक मानकों पर जोर देते हुए इस विचार का समर्थन किया।

ब्रिक्स देशों का उद्देश्य निष्पक्ष डेटा और व्यापक मूल्यांकन की कमी वाली वर्तमान रैंकिंग पर चिंताओं को दूर करना है, जिससे उन्हें एक स्वायत्त और विश्वसनीय विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली पर सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों ने एक स्वायत्त विश्वविद्यालय रेटिंग प्रणाली स्थापित करने का निर्णय क्यों लिया?

मंत्रियों ने वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए एक जवाबदेह और प्रासंगिक शिक्षा और प्रशिक्षण ढांचे की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने सामूहिक रूप से वर्तमान रेटिंग पद्धतियों की सीमाओं को स्वीकार किया और अधिक विश्वसनीय विकल्प की मांग की।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली मौजूदा रैंकिंग की आलोचनाओं को कैसे संबोधित करती है?

नई पहल का उद्देश्य व्यापक और निष्पक्ष डेटा को शामिल करना है, मौजूदा रैंकिंग की कमियों को सुधारना है जिन्हें अपने सीमित दायरे और निष्पक्षता की कमी के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है।

इस पहल में रूस के विज्ञान और उच्च शिक्षा उप मंत्री की क्या भूमिका है?

कॉन्स्टेंटिन मोगिलेव्स्की ने वैश्विक शिक्षा समुदाय में विश्वसनीयता और विश्वसनीयता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वस्तुनिष्ठ डेटा और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में निहित एक नए मूल्यांकन ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।

ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने नई रैंकिंग प्रणाली को अपना समर्थन क्यों दिया?

जवाबदेह दृष्टिकोण प्रदान करने की क्षमता के कारण इस पहल का समर्थन किया।

प्रस्तावित रेटिंग प्रणाली का लक्ष्य बेंचमार्क के संदर्भ में खुद को मौजूदा से अलग कैसे करना है?

चीन के उप शिक्षा मंत्री ने केवल मात्रात्मक मेट्रिक्स पर निर्भर रहने के बजाय गुणात्मक बेंचमार्क पर नई रेटिंग प्रणाली के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। यह अधिक समग्र और सूक्ष्म मूल्यांकन दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है।